newsprint from FINNPAP in October, 1991 at a FOB rate of $609 PMT, with option to purchase an additional quantity of 5000 MTs.

(ii) On 30 Dec., 1991, STC decided to exercise the option for purchase of this additional quantity of 5000 MTs from FINNPAP at the FOB rate of $609 PMT.

(iii) On the basis of a complaint received in January, 1992 that the international price was lower than $609 PMT FOB, the STC had advised the Supplier, FINNPAP not to go ahead with the production till such time they hear from STC in the matter.

(iv) STC is now seeking legal opinion before cancelling the contract for purchase of the additional 5000 MTs optional quantity.

Backing out from Commitments by Russians

44. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Russians are backing out from their commitments and many goods promised by former Soviet Russia found their way to hard currency areas;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have taken up the matter with successor States of Soviet Union;

(d) if so, the outcome thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (e) No, Sir. No formal indication has been given by Russia regarding not honouring commitments given by the erstwhile Soviet Union. There was, however, a shortfall in the supply of goods in 1991 due to various factors including the political changes in the erstwhile Soviet Union. The Government are fully seized of the matter and are making efforts to finalise separate trade agreements with the newly independent Republics. Agreements with the Russian Federation and Uzbekistan have already been signed.

Bungling by STC in Import of Newsprint

45. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item that appeared in the Times of India of 13th February, 1992 captioned 'Newsprint import case Belgium seizes SCI vessel wherein it has been stated that Shipping Corporation of India vessel has been seized as a consequence of bungling by STC in newsprint import case;

(b) if so, what are the details of the incident;

(c) what is the amount of loss likely to be suffered by India; and

(d) what are the details of action, if any, taken by Government against the STC officials?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) STC had imported some quantity of newsprint from M/s. Meteor Paper Ltd., London which was delivered through SCI. Due to a dispute in regard to declaration of the origin of material, manufacturer's certificate etc., STC did not release the payment to the supplier. On filing of a claim by the supplier against SCI for the value of cargo, one vessel of SCI was arrested at Antwerp (Belgium) on 12.2.92. The arrested vessel has since been got released by SCI on an indemnity bond.

(c) and (d) The matter is being investigated.

निर्यातकों को सुविधाएं और नई निर्यात नीति

46. **डा० अबरार अहमद:**
चौधरी हरि सिंह:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात में कृषि के लिए इस समय सरकार द्वारा निर्यातकों को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं और निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं और नई निर्यात नीति के अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यातकों को नकद प्रतिपूर्ति की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा;

(घ) क्या यह सच है कि नई वाणिज्यिक नीति से निर्यातक निराश हुए और निर्यात पर इसका विपरीत असर पड़ा है; और

(ङ) क्या सरकार अपनी वाणिज्यिक और निर्यात नीति में कोई संशोधन करने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) और (ख) एक विवरण पत्र संलग्न है। [नीचे देखिए]

(ग) विभिन्न वितरण प्राधिकारियों ने 1190 करोड़ रुपये के अतिरिक्त धन की अपनी आवश्यकताएं प्रदर्शित की है। इस आवश्यकता के आधार पर उन्हें 410 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं जो कि सी सी एस के लम्बित दावे का भुगतान करने के लिए उनकी आवश्यकता पर आधारित है।

(घ) सामान्यतः निर्यातकों ने जुलाई तथा अगस्त, 1991 में सरकार द्वारा घोषित व्यापार सुधारों का स्वागत किया है।

(ङ) आयात और निर्यात की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।

विवरण

निर्यातकों को सुविधाएं तथा नई निर्यात नीति

आयात तथा निर्यात नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के लाइसेंस पंजीकृत निर्यातकों को दिए जा रहे हैं:-

(i) वास्तविक निर्यातों—माने गए निर्यातों तथा सेवा निर्यातों के बदले में निर्यात पश्चात् आधार पर जारी एग्जिम स्क्रिप्स;

(ii) मान्यता प्राप्त निर्यात घरानों / व्यापार घरानों को जारी अतिरिक्त एग्जिम-स्क्रिप्स;

(iii) मान्यता प्राप्त शीर्ष व्यापार घरानों को विशेष अतिरिक्त एग्जिम-स्क्रिप्स;

(iv) शुल्क मुक्त योजना के अन्तर्गत निर्यात पूर्व आधार पर जारी विभिन्न लाइसेंस यथा अग्रिम लाइसेंस विशेष अग्रदाय लाइसेंस, ब्लैंकिट अग्रिम लाइसेंस मध्यवर्ती अग्रिम;

(v) तराशे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों के निर्यातकों को निर्यात-पूर्व आधार पर जारी हीरा। डी टी सी अग्रदाय लाइसेंस;

(vi) सोने तथा चांदी के आभूषणों के निर्यातकों को जारी रत्न एग्जिमा स्क्रिप्स;

(vii) सोने तथा चांदी के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया से प्राप्त किया जाने वाला रिलीज आर्डर;

(viii) सोने के आभूषण निर्यातकों को निर्यात-पश्चात् आधार पर जारी स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस;

(ix) सोने के आभूषण के निर्यातकों को निर्यात-पश्चात् आधार पर जारी स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस;

(x) निर्यात संसाधन क्षेत्रों / मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थित एककों तथा 100% निर्यातोन्मुखी एककों के रूप में अभिज्ञात एककों, जिन्हें पूंजीगत भाव, कच्ची सामग्री, संघटकों, फालतू पुर्जे आदि के आयात की अनुमति है, के लिए खुला सामान्य लाइसेंस। इसी नीति से, भारत के कुल निर्यातों में अप्रैल-दिसम्बर, 1990 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान 30.8% की वृद्धि हुई है।

Import Bill and Decanalisation of Raw Materials

47. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) what has been the import bill during the last 6 months as compared to the import bill of the previous 3 years;

(b) what are the items that come under the canalised imports alongwith the amount of import bill for the last 3 years;

(c) whether Government are considering the decanalisation of raw materials and putting them under OGL; and

(d) if so, what are the details thereof?